

कहना

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

किसी की आँख पुरनम है,
मुहब्बत हो गई होगी
जुबाँ पे फिस्सा-ए-गम है,
मुहब्बत हो गई होगी
कभी हँसना, कभी रोना,
कभी हँस हँस के रो देना
अजब दिल का ये आलम है,
मुहब्बत हो गई होगी
किसी को सामने पा कर,
किसी के सुर्ख होंटों पर
अनोखा सा तबस्सुम है,
मुहब्बत हो गई होगी
जहाँ वीरान राहें थीं,
जहाँ हैरान आँखें थीं
वहाँ फूलों का मौसम है,
मुहब्बत हो गई होगी
हर एक सिलवट पे बिस्तर की,
किसी का नाम लिखखा है
दिए की लौ मद्धम है,
मुहब्बत हो गई होगी।

- उमेरा अहमद

चुनाव से पहले नीतीश कुमार की घोषणाओं के पीछे क्या वजह?

उमेश कुमार राय

बिहार चुनाव की सरगमी से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश ने लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। पिछले एक महीने के दरम्यान उन्होंने करीब आधा दर्जन घोषणाएं की हैं, जिन्हें अमलीजामा पहनाने में बिहार सरकार के खजाने पर खासा बोझ बढ़ेगा। इनमें ताजा घोषणा प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देना है, मगर अन्य घोषणाओं के मुकाबले उनकी इस घोषणा की चर्चा कुछ अधिक है और इसकी वजह मुफ्त बिजली को लेकर उनका पुराना बयान है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन आप सरकार और अन्य राज्य सरकारों की इसलिए आलोचना की थी कि उन्होंने लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। दिलचस्प बात ये भी है कि मुफ्त बिजली देने की बिहार सरकार की मंशा और इस पर वित्त विभाग की सहमति को लेकर पिछले दिनों मीडिया में जब खबरें चली थीं, तो वित्त विभाग ने प्रेस नोट जारी कर स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं दी गई है। इस खंडन के तीसरे ही दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि बिहार सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि इससे 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। मुफ्त बिजली की घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने 21 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत एक करोड़ 11 लाख लोगों को मिल रही पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने

का ऐलान किया। इसी तरह, अगले पांच वर्षों में यानी 2025 से 2030 तक बिहार के एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा भी उन्होंने की। इसके अलावा सीएम ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरू करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को प्रति माह 3000 रुपये पेंशन देने और इंटरशिप करने के दौरान 12वीं पास युवाओं को 4000 रुपये, आईटीआई या डिप्लोमा पास युवाओं को 5000 रुपये और स्नातक व स्नातकोत्तर युवाओं को 6000 रुपये देने का ऐलान किया। गौरतलब है कि इन में से दो घोषणाएं - मुफ्त बिजली व पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का वादा इंडिया अलायंस के पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने आज से 6-7 महीने पहले ही किया था। तेजस्वी यादव ने दिसम्बर 2024 में ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो राज्य की जनता को हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उसी महीने तेजस्वी यादव ये भी कहा था कि उनकी सरकार आने पर वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये की जाएगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की इन घोषणाओं को चुनावी हार का टेंशन करार दिया। पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने कहा कि वहीं, मुफ्त बिजली की घोषणा पर तेजस्वी यादव ने कहा, 'महागठबंधन की सरकार आ रही है, इसी टेंशन में एनडीए सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाई है।' उन्होंने आगे कहा था, 'उनके पास न तो सोच है,

न विजन।' तेजस्वी ने आगे कहा था, 'हमने पहले ही मांग की थी कि हमारी घोषणाओं को बजट प्रस्ताव में शामिल किया जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे डर था कि श्रेय तेजस्वी ले जाएगा।' राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सुमन भी मानते हैं कि विपक्षी पार्टियों के चुनावी वादे के मद्देनजर ही नीतीश सरकार ने ये फैसले लिये हैं. वह कहते हैं। 'जाहिर है कि सरकार विपक्ष के मुद्दे छीन रही है।' तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड और अन्य राज्यों के तर्ज पर बिहार में माई-बहिन सम्मान योजना लाने का वादा भी कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि चुनाव से ठीक पहले इसी तरह की योजनाएं महाराष्ट्र, झारखंड, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने लागू की थीं, जिसका फायदा उन्हें मिला था और इन सभी राज्यों की सरकारों ने जीत दोहराई थी। इसके अलावा महागठबंधन सरकारी नौकरी में 100 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने का वादा भी कर रहा है, तो चर्चा है कि इस पर भी सरकार कुछ फैसले ले सकती है। हालांकि सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। नीतीश कुमार ने अपनी घोषणा में कहा है कि 125 यूनिट मुस बिजली देने से कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। जाति सर्वे 2022-2023 के मुताबिक, बिहार में कुल 2.766 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94.42 लाख परिवारों की मासिक आय 6 हजार रुपये व उससे कम है. वहीं, 81.91 लाख परिवारों की मासिक आय 6 हजार से 10 हजार रुपये के बीच

है। ऐसे में इस घोषणा से एक बड़ी आबादी को आर्थिक फायदा होगा। लेकिन, इस फैसले से बिहार सरकार पर खर्च का बोझ भी बढ़ेगा और बिजली सार्वजनिक बिजली कंपनियों और नुकसान झेलेंगी। 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दिये जाने से बिजली कंपनियों पर सालाना 4500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि बढ़ाने से अब बिहार सरकार को सालाना 9324 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया है, उस पर भी मोटी रकम खर्च होगी। अर्थशास्त्री इसे बिहार सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ के तौर पर देखते हैं और उनका कहना है कि इससे बिहार की आर्थिक सेहत पर खासा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार की इन घोषणाओं को जानकार दो तरह से देख रहे हैं। अव्वल तो ये माना जा रहा है कि जमीन पर सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है, जिसके चलते इस तरह की लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं और दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घोषणाएं भाजपा के दबाव में की जा रही है। नवल किशोर चौधरी कहते हैं, 'चूंकि विपक्षी पार्टियां भी सत्ता में आने के लिए लोकलुभावन वादे कर रही हैं, तो उसके जवाब में नीतीश सरकार को भी ऐसी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। आखिरकार उन्हें भी तो सत्ता बचानी है।' (दि क्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

संस्कृत को बोलचाल की भाषा बनाना जरूरी

● मागवत बोले- संस्कृत सभी भाषाओं की है जननी

कहा- इसे समझना ही नहीं, सबको बोलना भी चाहिए



नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब समय आ गया है कि इसे बोलचाल की भाषा बनाया जाए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संस्कृत को केवल समझना नहीं, बोलना भी आना चाहिए। भागवत ने कहा कि संस्कृत विश्व विद्यालय को सरकार

का सहयोग तो मिलेगा ही लेकिन असली जरूरत लोगों के सहयोग की है। उन्होंने माना कि वे संस्कृत जानते हैं लेकिन धाराप्रवाह बोल नहीं पाते। उन्होंने कहा कि संस्कृत को हर घर तक पहुंचाना होगा और इसे बातचीत का माध्यम बनाना पड़ेगा। संघ चीफ ने कहा कि आज देश में आत्मनिर्भर बनने की भावना पर आम सहमति है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि भाषा केवल शब्दों का माध्यम नहीं, बल्कि भाव होती है और हमारी असली पहचान भी भाषा से ही जुड़ी होती है। यह संस्थान संस्कृत को जीवंत रखेगा भागवत ने कवि कुलपुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में अभिनव भारती अंतरराष्ट्रीय अकादमिक भवन का उद्घाटन किया।

राज्यपाल श्री पटेल को स्काउट्स स्कार्फ पहनाकर किया सम्मानित



भोपाल (नप्र)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता में स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस राजभवन में शुक्रवार को मनाया गया। राज्यपाल श्री पटेल को इस अवसर पर स्कार्फ पहना कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्य अयुक्त श्री पारस जैन एवं अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विदित हो कि प्रतिवर्ष 01 अगस्त को स्काउट गाइड विश्व स्कार्फ दिवस मनाया जाता है। राज्यपाल, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य संरक्षक होते हैं।

नौ सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव

● इसी का ऐलान, 21 अगस्त तक भरे जाएंगे नामांकन

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अवानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। चुनाव आयोग की ओर से इसका पूरा शेड्यूल जारी किया है। इसके तहत 7 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल करने की डेट रहेगी। 22 अगस्त को नामांकन पत्र जांचे जाएंगे और 25 तारीख तक उन्हें वापस लिया जा सकेगा। यदि एक से ज्यादा उम्मीदवारों का नामांकन हुआ तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में 9 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसी दिन काउंटिंग होगी और शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की शाम को इस्तीफा दे दिया था।



मुख्यमंत्री सीहोर में आज 4 औद्योगिक इकाइयों का करेंगे भूमि-पूजन

सीहोर जिले में होगा लगभग 1440 करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 2 अगस्त शनिवार को सीहोर स्थित औद्योगिक क्षेत्र बड़ियाखेड़ी में लगभग 1406 करोड़ रुपये निवेश करने वाली 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 6 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी वितरित करेंगे। जिससे यहां लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपये का निवेश होगा। इन औद्योगिक इकाइयों से सीहोर जिले में 1165 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। 4 औद्योगिक इकाइयों का होगा भूमिपूजन- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन करेंगे। इन इकाइयों में सीहोर जिले में लगभग 1406 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 854 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जिन औद्योगिक इकाइयों का भूमि-पूजन होगा उनमें वाय्नावेदा ग्रीन्स जो (झिलेला) सीहोर में 20.020 हेक्टेयर में स्थापित होगी। इसमें 115 करोड़ रुपये के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी, जिससे 100 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार बारमाल्ट माल्टिंग इंडिया प्रा. लि. (बड़ियाखेड़ी फेस.2) 10.250 हेक्टेयर में स्थापित होगी। इसमें 400 करोड़ रुप

6 औद्योगिक इकाइयों को वितरित होंगे आशय पत्र

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीहोर में 6 औद्योगिक इकाइयों को आशय पत्र वितरित करेंगे, जिनमें आरटीडीबी इंडस्ट्रीज, स्वाति सोनी, संजय कुमार, अमित मूंदड़ा, प्रकाश पैकेजिंग और आरना वेचर्स शामिल हैं। इन इकाइयों द्वारा सीहोर जिले में लगभग 33 करोड़ 85 लाख रुपये का निवेश होगा और 311 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

के निवेश से देश की सबसे बड़ी माल्ट निर्माता कंपनी की इकाई स्थापित होगी, जिससे 350 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीजी पावर एंड इंजिनियरिंग सॉल्यूशन लि. (जहानगिरपुर) सीहोर में 18.260 हेक्टेयर में 888 करोड़ रुपए के निवेश से एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर इकाई स्थापित होगी, जिसमें 394 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार श्री कुष्णा इंडस्ट्रीज (बड़ियाखेड़ी) सीहोर 0.476 हेक्टेयर में 3 करोड़ रुपए के निवेश से खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी, जिससे 10 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का शीघ्र ही होगा प्रदेश आगमन: डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मिल रहा आशीर्वाद सभी प्रदेशवासियों के लिए उत्साहवर्धक है। प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भोपाल मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ और धार में आरंभ होने वाले प्रधानमंत्री मित्र पार्क के भूमिपूजन में स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद प्रदान करने की मौखिक सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से प्रदेश के किसान सम्मान कार्यक्रम में भी सहभागिता के लिए अनुरोध किया है। इन तीनों कार्यक्रमों के लिए शीघ्र ही प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिथि निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी से भेंट कर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया।

पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप मामले में दोषी करार

मैसूर (एजेंसी)। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोते प्रज्वल रेवन्ना को मेड से रेप मामले में दोषी ठहराया। कोर्ट शनिवार को सजा सुनायी। कोर्ट का फैसला आने के समय रेवन्ना भावुक दिखा और बाहर निकलते वक्त रो पड़ा। रेवन्ना के परिवार के फार्माइस में काम करने



वाली 47 साल की एक महिला ने पिछले साल अप्रैल में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने रेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने की किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी।

विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर

विशाखापट्टनम (एजेंसी)। गुगल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा। इसकी क्षमता 1 गीगावॉट होगी। फिलहाल देशभर में कुल 1.4 गीगावॉट क्षमता के डेटा सेंटर ऑपरेशनल हैं। रायटर्स के मुताबिक, गुगल इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसमें से 16 हजार करोड़ रुपए से रिन्युएबल एनर्जी से जुड़ी फेसिलिटी बनेगी। इसी से डेटा सेंटर को बिजली मिलेगी। अप्रैल में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कहा था कि वह इस साल दुनियाभर में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापट्टनम में तीन केबल लैंडिंग स्टेशन भी बनेंगे। इससे हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर हो सकेगा। राज्य में 1.6 गीगावॉट क्षमता के डेटा सेंटर निवेश को अंतिम



रूप दिया जा चुका है। अगले 5 साल में 6 गीगावॉट क्षमता के डेटा सेंटर तैयार करने का लक्ष्य है। डेटा सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है। बड़ी मात्रा में डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग के लिए कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बैंकिंग, खुदरा, स्वास्थ्य सेवा, टूरिज्म और अन्य ट्रांजेक्शन में बहुत अधिक डेटा मिलता है, जिसके स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है। इन सुविधाओं में डेटा स्टोरेज, सूचनाओं की प्रोसेसिंग और दूसरे स्थान पर उसे पहुंचाना और कंपनी के एप्लिकेशन से जुड़े काम काज शामिल हैं। इसे किसी सर्वर की तरह मान सकते हैं।

● एक गीगावॉट क्षमता होगी, गूगल 50 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा

सीएम ने किया स्मारिका विमोचन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने



विधानसभा में जन संवेदना समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया, इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल एवं सतीश सक्सेना सहित अन्य लोग शामिल हुए।

‘हमारा भोपाल–स्वच्छ भोपाल’ के अंतर्गत पौधारोपण



भोपाल। हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा आज पौधारोपण किया गया यह कार्य कलियासोत नदी के किनारे शिरडीपुरम साईं मंदिर के पास ग्रीन बेल्ट में पौधा रोपण किया गया। हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 6 साल पहले एक मुहिम शुरू की थीं। जिसका का नाम हमारा भोपाल–स्वच्छ भोपाल, ग्रीन भोपाल था। इसके अंतर्गत अभी तक संस्था द्वारा तकरीबन 160 पौधारोपण किया गया तथा लगातार उनकी देख रेख भी की उसके फलस्वरूप वह पौधे आज बड़े हो गए हैं। संस्था की इस मुहिम में संस्था के सदस्यों के अलावा शिरडीपुरम व अक्रीमेट कैम्पस के रहवासियों ने भी स्वयं आगे आके सहयोग किया। हिमांशु सोशल वेलफेयर सोसाइटी लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए कई स्कूल और रहवासी सोसायटी में जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित करती है।

हज–2026 के आवेदन की अंतिम तिथि 7 तक बढ़ी

विजयवाड़ा बना नया इम्बार्केशन पॉइंट, पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक होना अनिवार्य

भोपाल (नप्र)। हज-2026 के लिए इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा हज आवेदन की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 7 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक कर दिया गया है। यह जानकारी मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी (कैबिनेट मंत्री दर्जा) ने दी।

उन्होंने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 31 जुलाई को परिपत्र क्रमांक-6 जारी कर यह निर्णय लिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी।

इस वर्ष एक अहम बदलाव यह भी किया गया है कि देश के 17 इम्बार्केशन पॉइंट्स के साथ अब विजयवाड़ा को भी 30 जुलाई से एक नया इम्बार्केशन पॉइंट घोषित कर दिया गया है। जिन आवेदकों ने पहले से आवेदन कर दिया है और अब विजयवाड़ा को अपनी पसंद के रूप में चुनना चाहते हैं, वे आवश्यक बदलाव हेतु राज्य हज कमेटी से संपर्क कर सकते हैं।

रफत वारसी ने आगे बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होते ही हज यात्रियों के चयन के लिए डिजिटल कर्ग प्रक्रिया की जाएगी। इस प्रक्रिया में चयनित होने वाले प्रोविजनल हज यात्रियों को 20 अगस्त 2025 तक 1,52,300 रुप की अग्रिम राशि जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0755-2530139 पर संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट का अवलोकन करें।

भोपाल डिवीजन की हर चौथी ट्रेन लेट

पैसेंजर-मैमू सबसे पीछे, लेट हुई फिर भी वक्त पर पहुंची प्रीमियम ट्रेनें, रिपोर्ट में खुलासा

भोपाल (नप्र)। भोपाल रेल मंडल की जनवरी से जून 2025 तक की पंकुअलिटि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मंडल की ट्रेनों की औसत समय-पालन दर केवल 75.22त रही। इसका मतलब है कि हर चौथी ट्रेन देर से गंतव्य तक पहुंची। इस रिपोर्ट में प्रमुख ट्रेनों की समय-पालन स्थिति, रद्द/डायवर्ट/रीशेड्यूल की गई ट्रेनों और देरी के कारणों का ब्योरा दर्ज है।

प्रीमियम बनाम पैसेंजर ट्रेनों की समय-पालन दर प्रीमियम ट्रेनों की औसत पंकुअलिटि: प्रतिशत पैसेंजर ट्रेनों की औसत पंकुअलिटि: 58.39 प्रतिशत पिछले छह महीनों में भोपाल रेल मंडल से कुल 37,250 प्रीमियम ट्रेनें शेड्यूल की गईं, जिनमें से 7,649 ट्रेनें लेट हुईं। वहीं, 8,267 पैसेंजर ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 3,202 ट्रेनें देर से चलीं।

प्रीमियम और हाई-प्रोफाइल ट्रेनें, जिनमें बिजनेस क्लास, मिडिल क्लास और वोआईपी यात्री सफर करते हैं, अपेक्षाकृत समय की पाबंद हैं। दूसरी ओर, मैमू और पैसेंजर ट्रेनें, जिन्से मजदूर, किसान, कर्मचारी और विद्यार्थी यात्रा करते हैं, रोजाना लेट होती हैं।

हर चौथी ट्रेन रहती है लेट- भोपाल मंडल में प्रतिदिन औसतन 2.25 लाख यात्री 87 स्टेशनों से सफर करते हैं। ये यात्री लगभग 230 से 250 ट्रेनों में यात्रा करते हैं।

प्रमुख स्टेशनों से यात्री संख्या इस प्रकार है-

भोपाल में बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिल रहा

बगैर हेलमेट आए लोगों को लौटा रहे, टीमें निरीक्षण पर निकलीं

भोपाल (नप्र)। भोपाल में 1 अगस्त से बिना हेलमेट के टूट्हीलर्स चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह, बिना हेलमेट के सीएनजी गाड़ियों में भी गैस नहीं भरी जा रही है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने 30 जुलाई को यह आदेश जारी किया था। पहले दिन समझाइश का दौर भी देखने का मिल रहा है।

सुबह 11 बजे तक कई पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के भी पेट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन जब अफसरों की टीमें घूमने लगी तो पंप संचालकों ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दी। रवागिरी पेट्रोल पंप पर कई स्टूडेंट्स को भी लौटा दिया गया। वे हेलमेट पहनकर नहीं आए थे। पंपकर्मी मंजू गुर्जर ने बताया कि वह 100 से ज्यादा लोगों को लौटा चुकी है। उनसे कहा कि पहले हेलमेट पहनकर आए, तभी पेट्रोल भरेंगे।

न्यू मार्केट में दो पेट्रोल पंप पर भी यही तस्वीर नजर आई। पांच नंबर बस स्टॉप, एमपी नगर के पेट्रोल पंप भी लोगों को लौटा दिया गया। सख्ती के चलते कई वाहन चालक दूसरों से हेलमेट मांगकर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते भी नजर आए। बता दें कि भोपाल में कुल 192 पेट्रोल पंप हैं। जहां हर रोज पेट्रोल और डीजल की खपत 21 लाख लीटर है। इनमें से आधी से ज्यादा पेट्रोल की खपत होती है। इन पर अब बिना हेलमेट के



पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। पेट्रोल पंप कर्मी मंजू गुर्जर ने बताया कि बिना

हेलमेट हम पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। सबको मना कर रहे हैं। सुबह से हम कम से कम 100 लोगों को बोल चुके हैं, हेलमेट पहनने के बाद ही पेट्रोल मिलेगा।

पब में मिली युवती से शादी का वादा, फिर दुष्कर्म

भोपाल में ड्रम्स तस्कर यासीन पर एक और रेप केस, पीड़ित बोली- मुझे पीटा, वीडियो बनाए

भोपाल (नप्र)। भोपाल में ड्रम्स तस्कर यासीन अहमद उर्फ मछली पर रेप की एक और एफआईआर दर्ज की गई है। एक युवती ने शादी का झांसा देकर एक साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। पहली बार एमपी नगर के एक फाइव स्टार होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद अलग-अलग जगहों पर युवती के साथ ज्यादाती की गई।

आरोप है कि यासीन युवती को बेरहमी से पीटता था। उसने मारपीट के वीडियो भी बनाए थे। इन्हीं वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवती की पहचान की और उसकी काउंसलिंग कराने के बाद शुक्रवार को एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

इससे पहले महिला थाना और अरेरा हिल्स थाने में भी



यासीन अहमद उर्फ मछली

यासीन के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

पब में हुई थी युवती की यासीन से मुलाकात- सब इस्पेक्टर अर्चना तिवारी के मुताबिक 29 वर्षीय युवती प्राइवेट जॉब करती है। करीब एक साल पहले उसकी मुलाकात ड्रग तस्कर यासीन से एक पब में हुई थी। दोनों की बातचीत के बाद एक दूसरे से दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एक-दूसरे को अपने मोबाइल नंबर शेयर किए थे।

बाद में आरोपी यासीन ने युवती को मिलने के लिए एक फाइव स्टार होटल में बुलाया, जहां उसने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। उसके बाद से वह लगातार युवती का शोषण कर रहा था।

एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं

भोपाल–इंदौर में बूढ़ाबांदी का दौर रहेगा ; रायसेन में बाढ़ का असर रहा

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28 ईं वृष बारिश हो चुकी है, जो कोटे की 74 प्रतिशत है। पूर्वी हिस्से यानी- जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग में मानसून जमकर मेहबान रहा। इस वजह से बाढ़ के हालात भी बन गए। हालांकि, अब भारी बारिश का दौर थम गया है। स्ट्रॉन सिस्टम की एक्टिविटी नहीं होने से अगले 4 चार दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं है।

इससे पहले 15 से अधिक जिलों में हल्की बारिश का दौर जारी था। इनमें भोपाल, बैतूल, दतिया, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, दमोह, जबलपुर, मंडला, रीवा, बालाघाट, शाजापुर, सीहोर, देवास शामिल हैं। कहीं भी अति भारी या भारी बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रह सकता है। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है।

पूर्वी हिस्से में ज्यादा गिरा पानी- मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी हिस्से में अब तक 62 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में 55 प्रतिशत पानी ज्यादा गिर चुका है। रायसेन में बेतवा ने विकराल रूप लिया, खेत-मंदिर और पुल डूब गए- पिछले दो से तीन दिन तक रायसेन जिले में अति भारी बारिश का दौर रहा। गुरुवार को बारिश थमी, लेकिन हालात



गंभीर नजर आए। बेतवा नदी ने विशाल रूप ले लिया। आसपास के खेत, मंदिर और पुल डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही नजर आया।

श्योपुर में पार्वती नदी की बाढ़ में बहे चाचा-भतीजे के शव खेत में एक-दूसरे से लिपटे हुए मिले। शिवपुरी में माधव टाइन रिजर्व की सांख्य सागर झील ओवरफ्लो हो गई। सागर के देवरीकलां में संजय नगर स्थित रामघाट नाले में एक महिला बह गई। एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम पहुंची, जो सर्चिंग करती रही। वंदना साहू मालवार को सुबह 9 बजे नाग पंचमी पर रामघाट मंदिर में पूजन करके घर लौट रही थी। पुल पर से

गुजरने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गई थी।

खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेटों से पानी छोड़ा गया। इनमें 8 गेट 4 मीटर और 4 गेट साढ़े तीन मीटर तक खोले गए। पावर स्टेशन पर पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसके चलते नर्मदा में बाढ़ के हालात हैं।

खंडवा के मोरटक्का में प्राचीन जांबेश्वर महादेव मंदिर में पानी पहुंच गया। लोगों का कहना है कि बरसों से देखते आ रहे हैं कि नर्मदा मैसा हर साल जांबेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने आती है।

डॉ. नीलम के शरीर पर मिले 11 घाव, अभी हालत स्थिर

पानी का कैम्पर देने आता था आरोपी, कॉल पर सुना-डॉक्टर के देर से आने की बात

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर के श्रीकृष्णा परिसर की सातवीं मंजिल पर रहने वाली डॉ. नीलम सिंह पर बुधवार दोपहर एक युवक ने चोरी की नीयत से घुसकर चाकू से हमला कर दिया। अगर डॉ. नीलम 20 मिनट देर से घर पहुंचतीं, तो वह इस हमले से बच सकती थीं भले ही घर में चोरी हो जाती।

हमलावर मुकुल कहार ने यह सोचकर फ्लैट का दरवाजा खोला कि घर में कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही सामने डॉ. नीलम आईं, उसने अचानक चाकू से वार कर दिए। डॉक्टर की सर्जरी के दौरान शरीर पर 11 घाव मिले। खास बात ये है कि आरोपी डॉक्टर के संपर्क में तब आया था जब वह 15 दिन तक उनके घर पानी की कैम पहुंचाने आता था। इसी दौरान उसने डॉक्टर के आने-जाने का समय जान लिया और मौका देखकर हमला कर दिया।

पानी देने आता था आरोपी- डॉ. नीलम के पति धीरेंद्र सिंह, बिजली विभाग में कार्यरत हैं। जब पानी सप्लाई करने वाला पुराना व्यक्ति आना बंद हो गया, तो धीरेंद्र ने गृहाल पर नंबर खोजा और ऋषभ मिश्रा से बात हुई। ऋषभ ने मुकुल को पानी की कैम देने भेजा। मुकुल ने करीब 15 दिन तक रोज शाम को पानी पहुंचाया।

सोमवार को पानी की जरूरत खत्म होने पर धीरेंद्र ने ऋषभ से कह दिया कि अब पानी मत भेजें। मंगलवार को मुकुल आखिरी बार डॉक्टर नीलम के घर गया और वहां कोई और काम मिलने की उम्मीद जताई। नीलम ने कहा कि कोई काम नहीं है और वह घर चली जाए। उसी वक नीलम ने किसी से फोन पर कहा कि वह बुधवार को शाम 4 बजे तक घर पहुंचेंगी। मुकुल ने यह सुन लिया।

महिला का भेष लेकर पहुंचा आरोपी- बुधवार दोपहर करीब 3 बजे, मुकुल महिला के कपड़े और रेनकोट पहनकर अपार्टमेंट में घुसा। बारिश तेज थी और गाई अपने केबिन में बैठा था। मुकुल लिफ्ट से सीधा 7वीं मंजिल पर पहुंचा। उसे लगा कि डॉ. नीलम घर पर नहीं होंगी, लेकिन वे पहले ही लौट आई थीं।

जैसे ही मुकुल ने दरवाजा चाकू से खोलने की कोशिश की, नीलम ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। मुकुल को देखकर उन्होंने शोर मचाया तो उसने उन्हें धक्का दिया और अंदर घुस गया। कुछ देर संघर्ष के बाद उसने नीलम पर चाकू से हमला कर दिया। नीलम के पेट और सीने में 11 बार किए गए, जिससे वे जमीन पर गिर गईं।

महिला के भेष में होने से नहीं पहचान पाए गाई

सुरक्षा गाई ने बताया कि मुकुल महिला के भेष में आया था और तेज बारिश के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपार्टमेंट में रोज हाउस मेड आती हैं, इसलिए सभी पर नजर नहीं रखी जाती। मुकुल भी महिला समझकर आसानी से अंदर घुस गया।

सरकार के आदेश के बाद निर्णय

दो दिन पहले कलेक्टर सिंह के आदेश ने कहा गया है कि इस संबंध में समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मप्र मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी और वाहन चालक अनिवार्य रूप से आईएसआई मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेगा।

बिना हेलमेट पहने टूट्हीलर्स चलाने से हादसे की संभावना बनी रहती है। हेलमेट से जान काफी हद तक बच सकती है। कलेक्टर ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है।

इन्हें छूट मिली

प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंध के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और 29 सितंबर-25 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था और संचालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-23 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।

बिना हेलमेट पहनकर आने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन बिना हेलमेट के पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालक पर तो कार्रवाई करेगी, लेकिन जो पेट्रोल ले रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? सड़क पर पुलिस बिना हेलमेट वाले मोटरसाइकिल चालकों को नहीं पकड़ पा रही है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए।



पुलिस ने डोनेट किया ब्लड

डॉ. नीलम, जो कि कुछ समय पहले तक सीनियर रेजिडेंट थीं और अब ऑसिस्टेंट प्रोफेसर बनी हैं, को मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया। अभी तक 6 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया, जिसमें से 2 यूनिट पुलिस के जवानों ने डोनेट किया। डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और उनका ऑपरेशन सफल रहा है।

कातिल पर चलेगा फास्ट ट्रायल

सीएसपी आशीष जैन ने बताया कि मुकुल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह चोरी की नीयत से घुसा था। उसे लगा कि डॉक्टर घर पर नहीं होंगी, लेकिन समय से पहले लौटने पर उसने हमला कर दिया। मुकुल के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, ताकि उसे जल्दी और सख्त सजा मिल सके।

आईएमए ने किया हमले का विरोध

आईएमए अध्यक्ष डॉ. ऋचा शर्मा ने बताया कि नीलम को पेट और सीने में गहरे घाव आए हैं। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की है और समाज व डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की है। डॉक्टर नीलम को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया और डॉक्टरों की टीम ने समय रहते सर्जरी की। आईएमए और मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों ने इस हमले को कातिलाना हमला बताया है।

बेटा बोला - सोचा न था पिताजी मिलेंगे

पूरन सिंह जब गुम हुए थे, तब उनके बेटे राज सिंह की उम्र महज डेढ़ साल थी। उन्हें उनके चाचा ने पाला। परिवार ने पूरन सिंह को मृत मान लिया और खोजबीन की कोई खास कोशिश नहीं की गई। राज सिंह की परवरिश भोपाल और फिर महाराष्ट्र के मुलताई के पास हुई। अब वे एक मेडिकल स्टोर में काम करते हैं। जब राज सिंह को पता चला कि उनके पिता जीवित हैं और भोपाल में हैं तो कहा- कभी सोचा भी नहीं था कि पिताजी मिलेंगे। नानी का देहांत हो चुका है, और बाकी रिश्तेदारों से भी कभी पूरी जानकारी नहीं मिली। मुझे बस इतना पता था कि वो कहीं खो गए थे।

आश्रम संचालक ने

कहा- 8 महीने की सेवा

आसरा वृद्धाश्रम की व्यवस्थापक समीना मसीह ने बताया कि पूरन सिंह को जब लाया गया था, तो वे लावारिस हालत में थे। कहीं बेसुध पड़े हुए मिले थे। वो बार-बार यही बताते थे कि वे पुलिस में थे और ग्वालियर के किसी गांव से हैं, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं था। न बेटे का नाम, न पत्नी का। उन्होंने कहा कि आठ महीनों से आश्रम में उनकी पूरी सेवा की गई। डॉक्टरों की मदद से उनकी हालत कुछ सुधरी और तभी धीरे-धीरे बातें सामने आने लगीं।

संपादकीय

भगवा आतंक का नरेटिव खारिज

महाराष्ट्र के माले गांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद आए विशेष एनआईए अदालत के फैसले ने जहां भगवा आतंकवाद’ के सुनियोजित नरेटिव को खारिज कर दिया है, वहीं इस सवाल को जिंदा रखा है कि इस आतंकी हमले में 6 लोगों को आखिर किसने मारा? पूरी जांच इस मामले में मौन लगती है। हालांकि इस मामले में बरी आरोपी और भाजपा इसलिए खुश हैं कि तत्कालीन संप्रग सरकार ने परोक्ष रूप में देश में जारी आतंकवाद का बचाव करने के लिए ‘भगवा आतंकवाद’ जैसा नरेटिव गढ़ा, इससे यूपीए और खासकर कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलने की बजाए भारी नुकसान ही हुआ, जिसकी भरपाई अभी भी नहीं हो पा रही है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यह ठीक भी है कि अगर मालेगांव ब्लास्ट कांड में अतिवादी आतंकवाद था तो एक पखवाड़े जिस मुंबई बम ब्लास्ट कांड में सभी आरोपी बरी हुए, वो क्या था? मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी, जिसके तत्कालीन मुखिया हेमंत करकरे को मालेगांव ब्लास्ट के कुछ महीने बाद ही हुए मुंबई आतंकी हमले में मार दिया गया था। 2011 में इसकी जांच एनआईए को सौंपी गई। मालेगांव की एक मस्जिद के बाहर हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत और सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस कांड के सबसे चर्चित आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित थे, जिन पर आरोप था कि वो संघ से जुड़े हैं और उन्होंने ‘अभिनव भारत’ नामक संस्था बनाकर हिंदू युवाओं को आतंकी हमले की ट्रेनिंग दी थी। इस मामले में चार एजेंसियां बदलीं। 2014 में दिल्ली में मोदी सरकार के सत्तासीन होने के बाद इस बात का अंदाजा हो गया था कि इस मामले में दोष सिद्ध करना कठिन होगा। इस प्रकरण के 323 गवाहों में से 37 अदालत में बयान से मुकर गए। अपना फैसला सुनाते हुए विशेष एनआईए जज ने कहा कि सरकारी पक्ष यह तो साबित कर सका कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन यह साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल पर ही लगाया गया था।

दावा किया गया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित कश्मीर से आरडीएस लेकर आए थे, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह भी साबित नहीं हो सका कि पुरोहित ने अपने घर पर बम तैयार किया था। रमजान की वजह से उस समय इलाका बंद था, और यह स्पष्ट नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल वहां कैसे पहुंची। ऐसा कहा गया कि ईदौर, उज्जैन और नासिक जैसे स्थानों पर साक्षिज्ञ रचने के लिए बैठकें हुई थीं, लेकिन ऐसी बैठकों का कोई विश्वसनीय प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया जा सका। अदालत ने यह भी पाया कि जांच अधिकारियों ने फ़ोन रिकॉर्ड की जांच के लिए अनुमति नहीं ली थी। अभिनव भारत मामले में पुरोहित, राहिरकर और उपाध्याय के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन के प्रमाण तो मिले, लेकिन यह साबित नहीं हो सका कि उस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में किया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह यह एक गंभीर अपराध था, लेकिन फैसला सुनाने के लिए ठोस और निर्विवाद प्रमाण की आवश्यकता होती है। केवल नैतिक आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले के खिलाफ एनआईए बड़ी अदालत में जाएगी, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन पीडित पक्ष जा सकता है। अलबत्ता इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं के सुर जरूर बदल गए हैं। जिस भावा आतंकवाद की बात उन दिनों जॉर-शोर से कही जा रही थी, उस पर ये नेता अब दाएं बाएं हो रहे हैं। क्योंकि भगवा आतंकवाद के लपेटे में सभी हिंदुओं को लेना बहुत बड़ी राजनीतिक चूक थी।

बिहार में बाहरी वोटर, माजरा क्या है?

विधानसभा चुनाव

योगेन्द्र यादव

लेखक प्रख्यात चुनाव विश्लेषक हैं।

वूँ तो हमारे देश में शिगुफ़ों की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन पिछले दस साल में तो जैसे शिगुफ़े खिलाना एक राष्ट्रीय शगल हो गया है। आपको कोविड का दौर याद है? लॉकडाउन की शुरुआत में ही दिल्ली की ‘निजायुद्दीन मस्जिद’ में ‘तलबीगी जमात’ के एक सम्मेलन से कोविड फैलाने की अफवाह चली थी। सरकारी और दबबारी हर स्रोत से खूब शिगुफ़ उछलते गए थे। अच्छे-अच्छे इस खबर का शिकार हो गए थे। फिर पाँच साल बाद इस महीने अदालत का फैसला आया कि सारी बात कोरी गप थी। पुलिस की चार्जशीट में कोविड का जिक्र भी नहीं था, लेकिन तब तक किसी परवाह की शेल खल हो चुका था, ‘टीआरपी’ (टाइम रेटिंग प्वाइंट) हज़म हो चुकी थी।

ठीक इसी तर्ज पर अब बांग्लादेशी वोटरों का शिगुफ़ा उछला जा रहा है। झारखंड के चुनाव में भाजपा के प्रभारी हेमंत बिस्वा सरमा ने खूब खुलकर बांग्लादेशी वोटर का कार्ड खेला। चला नहीं। किसी को ढूँढने पर भी झारखंड में बांग्लादेशी नहीं मिलता था। यही खेल रोहिंया के नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ। पिछले हफ्ते यही खेल हरियाणा के गुडगांव में खेला गया। पता लगा कि पुलिस की इस मुहिम के शिकार हुए लगभग सभी लोग बांग्लाभाषी भारतीय नागरिक थे, गरीब थे, मजदूरी कर अपना पेट पालते थे। अब यही खेल बड़े पैमाने

पर बिहार में खेला जा रहा है। जबसे बिहार में मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) की शुरुआत हुई है, तबसे मीडिया में यह अभियान चल रहा है कि इस पुनरीक्षण का असली उद्देश्य बिहार में विदेशी नागरिकों की पहचान कर वहाँ की वोटर लिस्ट में घुसे बांग्लादेशी और ग्यांमार के नागरिकों को बाहर निकालना है।

बिहार के पूर्वोत्तर की पूर्णिया कमिश्नरी में चार जिले हैं – पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। एक तरफ नेपाल और दूसरी तरफ बंगाल से सटे इस क्षेत्र को ‘सीमांचल’ कहा जाता है। यहीं मुस्लिम जनसंख्या बाकी बिहार से बहुत ज्यादा है। कुछ इलाकों में मुस्लिम बहुमत भी है। पिछले कई हफ्तों से ‘चुनाव आयोग’ के ‘सूत्रों’ के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम दरअसल ‘सीमांचल’ में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है। वैसे यह पूछ जाना चाहिए था कि सिर्फ चार जिलों के कुछ घुसपैठियों को खोज निकालने के लिए पूरे बिहार के आठ करोड़ मतदाताओं को परेशान करने की क्या जरूरत थी? ‘चुनाव आयोग’ के पास अधिकार है कि वो चंद जिलों या तहसीलों की वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकता है। वो क्यों नहीं किया? पूछा यह भी जाना चाहिए था कि पिछले 11 वर्षों से इस देश की सरकार कौन चला रहा है? अगर अब भी वोटर लिस्ट में धांधली है तो जिम्मेदारी किसकी है?

खैर, इस सब तर्क-कुत्तर्क को छोड़कर टंडे दिमाग से इस सवाल पर विचार करें, ताकि दिन-रात उछलते जाने वाले शिगुफ़ों से बच सकें। सबसे पहले तो बिहार का नक्शा देखिए और पृष्ठिए कि बिहार में अगर अवैध विदेशी घुसपैठे तो कहीं से आयेगे? पलक झपकते ही आप जान

जाएँगे कि बिहार की सीमा बांग्लादेश से नहीं, नेपाल से मिलती है। बेशक ‘सीमांचल’ से बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है और वहाँ से आवाजाही भी असंभव नहीं है, लेकिन नेपाल से तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। बिहार के सात जिलों की 726 किमी सीमा नेपाल से लगती है जो अभी भी खुली है और नेपाल के नागरिकों को भारत में बिना वीजा के घुसने और रहने का अधिकार है। दोनों तरफ़ रोटी-बेटी के संबंध हैं। नेपाल की लाखों बेटीयां भारतीय बहू हैं और बसों से वोट दे रही हैं। जरा सोचिए, अवैध विदेशियों की सारी चर्चा बांग्लादेश की क्यों है, नेपाल की क्यों नहीं? चिंता विदेशी की है या मुसलमान की?

नक्शे को छोड़िये, आर्थिक स्थिति देख लीजिए। पिछले दो दशकों में बांग्लादेश की स्थिति बदल गई है। वर्ष 2024 में बिहार की प्रति व्यक्ति मासिक आय सिर्फ़ 5,570 रुपए थी। सीमांचल के जिलों में उससे भी कम रही होगी। उसी वर्ष बांग्लादेश को प्रति व्यक्ति मासिक आय 19,200 भारतीय रुपए के बराबर थी, यानी बिहार से कोई चार गुना ज्यादा। दुनिया भर में लोग बदहली से बचने के लिए खुशहाल इलाकों में जाते हैं। आप जरा सोचिए किसी बांग्लादेशी की मत मारी होगी कि वो अपना घर और देश छोड़कर, जोखिम उठाकर अपने यहाँ से बदहली की स्थिति में जीने के लिए बिहार आए? अब आइए ‘ह्यूडरपेपे यूनिवर्सिटी’ पर। आपने सुना होगा कि बिहार के इन चार मुस्लिम बहुल जिलों में आबादी से भी अधिक ‘आधार कार्ड’ बने हैं, यानी कुछ विदेशी घुसपैठियों ने बनवाये हैं। इसकी सच्चाई जांचने के लिए आप साबसे आर्थरिटी की वेबसाइट देख लीजिए। चार जिलों में नहीं, बिहार के 38 में से 37 जिलों में कुल जारी हुए ‘आधार कार्ड’ की संख्या

अनुमानित आबादी से ज्यादा है। यहीं नहीं, पूरे देश में अनुमानित आबादी 141 करोड़ है और ‘आधार कार्ड’ 142 करोड़ और इसका किसी घुसपैठिये या विदेशी से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका कारण है कि इन ‘आधार कार्डों’ में से कोई एक दहाई मृत लोगों के नाम हैं। यानी यह शुद्ध शिगुफ़ा है।

अब सीधे वोटर लिस्ट की बात कर लें। संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए 10 जुलाई 2019 को सरकार ने बताया था कि पिछले तीन वर्ष में ‘चुनाव आयोग’ को पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सिर्फ़ तीन विदेशी नागरिक मिले थे – एक गुजरात, एक बंगाल और एक तेलंगाना में। इस वर्ष जनवरी के महीने में बिहार की वोटर लिस्ट का जो परीक्षण पूरा हुआ, उसके बाद ‘चुनाव आयोग’ ने बिहार के जिलेवार वोटर और जनसंख्या के आंकड़े जारी किए। ‘सीमांचल’ के चार जिलों की स्थिति बाकी बिहार से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। छह महीना पहले हुए उस परीक्षण में चुनाव आयोग को बिहार में एक भी विदेशी नागरिक होने का प्रमाण नहीं मिला। एक नाम भी नहीं कटा।

और हाँ, चार हफ्ते तक बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार का प्रचार होने के बाद ‘चुनाव आयोग’ ने सुप्रीम कोर्ट में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ के बारे में 789 पेज का हलफनामा दायर किया है। आप जानना चाहेंगे, उसमें विदेशी घुसपैठियों के बारे में क्या लिखा गया है? एक शब्द भी नहीं। एक महीने की कवायद पूरी होने के बाद ‘चुनाव आयोग’ ने 7 करोड़ 89 लाख लोगों के आंकड़े जारी किए हैं – जिनके फॉर्म भरे गए, जो मर गए, जो अन्य राज्य में चले गए, जो दुस्लीकेट हैं, जिनका अता-पता नहीं है। आप जानना चाहेंगे, इनमें विदेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी है? शून्य! इसे कहते हैं शिगुफ़ा! (सप्रेस)

अनुमानित आबादी से ज्यादा है। यहीं नहीं, पूरे देश में अनुमानित आबादी 141 करोड़ है और ‘आधार कार्ड’ 142 करोड़ और इसका किसी घुसपैठिये या विदेशी से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका कारण है कि इन ‘आधार कार्डों’ में से कोई एक दहाई मृत लोगों के नाम हैं। यानी यह शुद्ध शिगुफ़ा है।

अब सीधे वोटर लिस्ट की बात कर लें। संसद में एक प्रश्न का जवाब देते हुए 10 जुलाई 2019 को सरकार ने बताया था कि पिछले तीन वर्ष में ‘चुनाव आयोग’ को पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सिर्फ़ तीन विदेशी नागरिक मिले थे – एक गुजरात, एक बंगाल और एक तेलंगाना में। इस वर्ष जनवरी के महीने में बिहार की वोटर लिस्ट का जो परीक्षण पूरा हुआ, उसके बाद ‘चुनाव आयोग’ ने बिहार के जिलेवार वोटर और जनसंख्या के आंकड़े जारी किए। ‘सीमांचल’ के चार जिलों की स्थिति बाकी बिहार से बिल्कुल भी अलग नहीं थी। छह महीना पहले हुए उस परीक्षण में चुनाव आयोग को बिहार में एक भी विदेशी नागरिक होने का प्रमाण नहीं मिला। एक नाम भी नहीं कटा।

और हाँ, चार हफ्ते तक बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भरमार का प्रचार होने के बाद ‘चुनाव आयोग’ ने सुप्रीम कोर्ट में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ के बारे में 789 पेज का हलफनामा दायर किया है। आप जानना चाहेंगे, उसमें विदेशी घुसपैठियों के बारे में क्या लिखा गया है? एक शब्द भी नहीं। एक महीने की कवायद पूरी होने के बाद ‘चुनाव आयोग’ ने 7 करोड़ 89 लाख लोगों के आंकड़े जारी किए हैं – जिनके फॉर्म भरे गए, जो मर गए, जो अन्य राज्य में चले गए, जो दुस्लीकेट हैं, जिनका अता-पता नहीं है। आप जानना चाहेंगे, इनमें विदेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी है? शून्य! इसे कहते हैं शिगुफ़ा! (सप्रेस)

कटाक्ष

राजेंद्र नामर ‘रिस्तर’

लेखक व्यंग्यकार हैं।

‘क वि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जाग में उथल-पुथल मच जाए’ इन पंक्तियों के लेखक पं. बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने शायद यह सोचकर इन पंक्तियों का निर्माण किया होगा कि कवि की शक्तिशाली लेखनी चलेगी तो दुनिया में होने वाली तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। शांति छ जाएगी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं।

सैकड़ों बरसों से कवि,साहित्यकार, चिंतक, विचारक, आलोचक पूरे विश्व की समस्याओं पर चाहे वह परमाणु बम हो या मानवाधिकार, खूब लिख रहे हैं लेकिन उथल-पुथल तो छोड़ो एक छोटा सा झटका भी महसूस नहीं होता। हां साहित्यकार महोदय जरूर अपनी रचना को लोगों को सुना-सुना कर उछलते कूदते रहते हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाले,लोकल अखबार में छपकर अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का कवि समझने वाले वीर रस के कवि दिग्विजय जी ने चार छंद लिखकर सोचा कि शायद महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम हो जाएँगे। देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। लिहाजा जैसा सब चरों में होता है, उनकी सबसे पहली श्रोता बनी उनकी अपनी पत्नी, जिसने रोटी बनाते बनाते ‘ठीक है’ कहते हुए कविता को पास आँन कर दिया। दूसरी श्रोता बनी पड़ोसी की पत्नी जिसे अभी-अभी साहित्यकार बनने का कीड़ा काटना

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ

शुरू हुआ था। उन्हें तो वाह वाही करनी ही थी। फिर शुरू हुआ स्थानीय अखबार के परिचित संपादक से कविता को छपवा कर उसके प्रचार का दौर। बोशर नुमा उस साप्ताहिक के छपते ही वह शाम को गली के चौराहे पर आकर खड़े हो गए कि शायद लोग उन्हें पहचान लेंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा पर सिवाय तीन कुत्तों के जिन्हें वे रोज बिस्किट देते थे कोई उनके पास नहीं आया। फिर उन्होंने चाय पान की दुकान और रेलवे स्टेशन पर घूमना शुरू किया। कहीं कोई हलचल नहीं। आखिर उन्होंने एक से पूछ ही लिया कि आज उनका महिला अत्याचार पर एक गीत छपा है। पढ़ा क्या ?

किसी ने टाइम नहीं होने की बात कही तो किसी ने उन्हें पागल समझ लिया। अंत में उन्होंने सोशल मीडिया की मदद ली। व्हाट्सएप पर सबको शेयर करने के बाद उन्होंने यह अपील भी की कि इस गीत को दस लोगों तक जरूर पहुंचाएं। प्रधानमंत्री तक बात पहुंचनी चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि अब जरूर पूरा देश हिल जाएगा लेकिन सिवाय उनकी पत्नी,साली और बेटी के अलावा किसी ने लाइक नहीं किया। बल्कि लड़के ने तो दो बातें और सुना दी।

एक कवि हुए तोथानंद जी। उन्होंने आध्यात्मिक गीत लिखकर देश में हिंदुत्व की लहर जगाने का प्रयास किया लेकिन बरसों से सोया हिंदू तो प्रसार का दौर। बोशर नुमा उस साप्ताहिक के छपते ही वह शाम को गली के चौराहे पर आकर खड़े हो गए कि शायद लोग उन्हें पहचान लेंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा पर सिवाय तीन कुत्तों के जिन्हें वे रोज बिस्किट देते थे कोई उनके पास नहीं आया। फिर उन्होंने चाय पान की दुकान और रेलवे स्टेशन पर घूमना शुरू किया। कहीं कोई हलचल नहीं। आखिर उन्होंने एक से पूछ ही लिया कि आज उनका महिला अत्याचार पर एक गीत छपा है। पढ़ा क्या ?

किसी ने टाइम नहीं होने की बात कही तो किसी ने उन्हें पागल समझ लिया। अंत में उन्होंने सोशल मीडिया की मदद ली। व्हाट्सएप पर सबको शेयर करने के बाद उन्होंने यह अपील भी की कि इस गीत को दस लोगों तक जरूर पहुंचाएं। प्रधानमंत्री तक बात पहुंचनी चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि अब जरूर पूरा देश हिल जाएगा लेकिन सिवाय उनकी पत्नी,साली और बेटी के अलावा किसी ने लाइक नहीं किया। बल्कि लड़के ने तो दो बातें और सुना दी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जौन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज सुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI NO. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph. No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे सम्बाध पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

(अब श्रद्धा भी पैकेज में उपलब्ध है)

सचिन सिंह परिहार

(लेखक एवं राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी)

सावन का महीना चल रहा है। चारों ओर भक्ति का उत्सव है। भगवान शिव को गंगाजल, बेलापत्र, दूध और अब डाटा पैक चढ़ाया जा रहा है। मैंने सोचा, इस बार सावन में एक सच्चे श्रद्धालु बनते हैं। चम्पल बाहर, मोबाइल भीतर। ऐसी भक्ति करनी है कि भोलेनाथ भी आकाशगंगा से झोंकें और कहें, ‘बेटा, तुम तो सच में जुड़े हुए लगते हो।’ लेकिन मंदिर पहुँचा, तो अनुभव हुआ कि अब शिवालय केवल ईश्वर का वास नहीं, बल्कि आधुनिक युग का भक्ति केंद्र बन चुका है। एक युवक दिखा। गले में रुद्राक्ष की माला, कानों में छोटे यंत्र, हाथ में कांवड़ और उंगलियों से सीधा प्रसारण चला। बम बम भोले बोलते हुए कह रहा था ‘मित्रों, हम अभी दर्शन करवा रहे हैं। कृपया इसे सबके साथ साझा करें, और ध्यान रखें कि घंटी वाला चिन्ह दबाना न भूलें।’ पास ही एक वृद्ध महिला आँखें मूँट खड़ी थीं। पर कैमरे के दृश्य में न होने के कारण उनकी श्रद्धा मानो महत्वहीन हो गई थी। श्रद्धा की दुकान और स्टूट का आकर्षण मंदिर के बाहर एक स्टॉल सजा था। ऐसा लग रहा था जैसे

किसी बड़े ऑनलाइन बाज़ार की शाखा हो। ‘हर हर महादेव विशेष पैकेज केवल नौ सौ निन्यानवे रुपये हैं!’ इसमें मिलेगा पाँच सेकंड में दर्शन, एक सुंदर फोटो फ्रेम, और पंडित जी का ऐसा आशीर्वाद जो किसी तस्वीर के लिए उपयुक्त हो। एक युवक अपनी कमीज पर लिखावा रहा था ‘भोले बाबा ने मुझे अनुसरण किया है।’ कहीं और कैसे? शायद किसी सामाजिक मंच पर। मंदिर के प्रांगण में कथा चल रही थी। पंडित जी गंभीर आवाज़ में बोले ‘शिव वही हैं, जो बाह स्वीकार करते हैं।’ भोड़ में से कोई बोला ‘थोड़ा ज़ोर से बोलिए पंडित जी, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही।’ अब कथा नहीं रही, दृश्य सामग्री बन गई है। जहाँ भावनाएं उच्च गुणवत्ता के कैमरे में कैद होती हैं, और मोक्ष किसी यंत्र से सम्पादित किया जाता है। भक्तों की टोली आई। कांवड़, थिक्कते शरीर, और ऊँची

अमेरिकी हस्तक्षेप से मुक्ति की दिशा

वास्तव में शांतिप्रिय मध्य एशिया में तबाही,बर्बादी व अशांति की इबारत लिखने वाला अमेरिकी संरक्षित इस्राइल ही है। 7 अक्टूबर 2023 को जब से दक्षिणी इस्राइल पर हमास द्वारा हमले किये गये और 251 लोगों को बंधक बनाया गया उसके बाद इस्राइली सेना (आईडीएफ) ने हमास की आतंकी कार्रवाई के जवाब में जिस तरह गाज़ा पट्टी में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की और आज तक जारी है उसने इस्राइल व अमेरिका के अमानवीय चेहरे को पूरी तरह उजागर कर दिया है। गाज़ा में बर्बरता और अत्याचार की हर सीमाओं को इस्राइल पार कर चुका है। रिहाइशी बस्तियों अस्पतालों स्कूलों शरणार्थी कैपों धर्मस्थलों आदि को खंडहर बनाने के बाद अब भूखे निहत्थों को मार रहा है।

संगठनों और मानवाधिकार समूहों का कहना है कि गाज़ा में बड़े पैमाने पर मानव जनित भूखमरी फैल रही है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन हालात के लिए इस्राइल को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि वही फ़िलस्तीनी क्षेत्रों में भेजी जाने वाली सप्लाई को नियंत्रित करता है। आम लोग ही नहीं बल्कि गाज़ा में युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले अनेक स्थानीय व विदेशी पत्रकार व उनका परिवार भी भूखमरी का सामना करने को

मजबूर है। कुछ पत्रकार तो इस हद तक असहाय हो चुके हैं कि वे अपने मासूम असहाय बच्चों व परिवार के लिए भोजन तक नहीं जुटा पा रहे हैं। गाज़ा में काम करने वाले कुछ पत्रकार तो अपनी जान की बाजी लगाकर लाइनों में लगकर चैरिटी किचन से खाना ले रहे हैं। उनके बच्चे दिन में सिर्फ़ एक बार दाल, चावल या पास्ता खा कर गुज़ारा करने को मजबूर हैं। कुछ पत्रकारों ने तो यहाँ तक बताया कि उन्होंने भूख दबाने के लिए नमक मिला पानी पीना शुरू कर दिया है। ज़रा सोचिये जिन पत्रकारों की बदौलत दुनिया को इस्राइली सेना के जुल्म और गाज़ा के लोगों की बेबसी व बर्बादी की खबर सुनाई व दिखाई देती थी अगर वही पत्रकार व उनका परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा तो अमेरिकी संरक्षित इस्राइल के काले करतूत दुनिया तक कैसे पहुंचेंगे ? इन्हीं हालात में अनेक अंतराष्ट्रीय राहत

संगठन और मानवाधिकार समूह बड़े पैमाने पर भूखमरी फैलने की चेतावनी दे रहे हैं। एक ओर तो इस्राईल-अमेरिका फ़िलिस्तीनियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हमास को आतंकी संगठन बताकर उसकी आड़ में पूरे फ़िलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल करने की फ़िराक में है तो दूसरी ओर यही इस्राईल-अमेरिका अहमद हुसैन अल-शरा, जिसे अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से भी जाना जाता है,को सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटकर

व अमेरिकी रहस्यो कर्म पर जीने वाले कुछ अमेरिकी पिड्ड देशों की शासकों व तानाशाहों की बात छोड़ दें तो पूरा विश्व खासकर मध्य एशियाई देश इस बात को समझ चुके हैं कि अब समय आ गया है कि किसी भी तरह इस्राइल को सबक सिखाया जाये और मध्य एशियाई क्षेत्रों को अमेरिकी हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाई जाये। ईरान का भय दिखाकर सुन्नी शिया मतभेदों को बढ़ावा देना दरअसल अमेरिका की सुन्नी देशों के प्रति हमदर्दी नहीं बल्कि एक बड़ी चाल है जिसे मुस्लिम जगत अब बखूबी समझ चुका है। मुस्लिम जगत जुलानी की आड़ में सीरिया को बर्बाद करने की साजिश को भी समझ रहा है। परन्तु ख़बर यह भी है कि सीरियाई जनता भी अमेरिका इस्राइल के सीरिया के प्रति नापाक इरादों को भांप कर एकजुट होने लगी है। मध्य एशियाई क्षेत्रों को अमेरिका से मुक्त कराने के शुरुआत संकेत मिलने लगे हैं। ईरान ने गत 23 जून को क़तर की राजधानी दोहा स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे अल-उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दाग़ कर तथा इराक़ और सीरिया में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना कर यह चेतावनी दे दी है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे मध्य एशियाई क्षेत्रों में सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही इराक़ी प्रतिरोध समूहों, विशेष रूप से क़ताइब हिज़बुल्लाह, ने इराक़ी सरकार को यह चेतावनी जारी कर दी है कि वह अमेरिकी सेना को दो महीने के भीतर बग़दाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऐन अल-असद बेस जैसे इराक़ी सैन्य ठिकानों, से पूरी तरह से हटने के लिए कहे। इराक़ी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी को इस संबंध में पहले से सहमति के आधार पर कार्रवाई करने के लिए ‘पर्याप्त समय’ दिया गया था, और अब केवल दो महीने बचे हैं। यानी सितंबर 2025 के अंत तक अमेरिका को इराक़ छोड़ने की चेतावनी दे दी गयी है। इस चेतावनी में यह भी कहा गया है कि अगर यह कार्रवाई समय सीमा में पूरी नहीं हुई, तो उनकी ‘अलग राय’ होगी, हालांकि उन्होंने ‘अलग राय’ को स्पष्ट नहीं किया।इस तरह की अनेक छोटी बड़ी घटनाओं व अंतराष्ट्रीय स्तर पर हो रही गोलबंदी को देखते हुये इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि मध्य एशिया अमेरिकी हस्तक्षेप से मुक्ति के प्रयास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

कराची में राम का आगमन	
डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुलेरे	
	

जहाँ गोलियों की गूँज थी, वहाँ रामायण का मंचन हुआ – पाकिस्तान के दिल कराची में, राम की कथा ने फिर से स्मृति और संवाद के द्वार खोले। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या और भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ‘सिंदूर’ की सैन्य प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के संबंधों को और विषाक्त बना दिया है। इसी पृष्ठभूमि में, कराची में एक शांत और विलक्षण सांस्कृतिक घटना घटित हुई – वहाँ के ‘मौज’ थिएटर समूह ने पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में हिंदू महाकाव्य ‘रामायण’ का सफल मंचन किया।

यह कोई मामूली घटना नहीं थी। एक ऐसे समय में जब सीमाएँ केवल कंट्रीले तारों से नहीं, बल्कि डर और नफरत से भी जकड़ी जा रही हैं – कराची में रामायण का मंचन, कलात्मक साहस और सामाजिक स्मृति की एक जीवंत झलक है।

कलाकार मुसलमान, कथा राम की
इस नाट्य प्रस्तुति की एक और विशेष बात यह थी कि इसके सभी कलाकार पाकिस्तानी मुसलमान थे। केवल निर्देशक, योगेश्वर करेरा, एक हिंदू थे, और निर्माता राणा काजमी, एक उद्यार और दूरदर्शी पाकिस्तानी मुसलमान। कराची जैसे शहर में, जहाँ सांस्कृतिक विविधता धीरे-धीरे सिकुड़ती जा रही है, वहाँ एक समर्पित मुस्लिम टीम द्वारा रामायण का मंचन किसी साम्प्रदायिक सहयोग नहीं, बल्कि साझा विरासत की



पुनरावृत्ति जैसा था।

यह दर्शकों के लिए भी एक प्रयोग था। मंचन के दौरान ‘मुद्रिका’ जैसे शब्द पर जब कुछ दर्शक अचकचाए, तो यह स्पष्ट हुआ कि सांस्कृतिक शब्दावली भी बँटती है, मिटती है, और फिर कभी-कभी लौटती भी है।

स्मृति का एक पुराना पन्ना
इस रामायण की गूँज हमें एक और याद दिलाती है –

1987-88 के वह रविवार, जब भारत ही नहीं, पाकिस्तान की गलियाँ भी सूनी हो जाती थीं, क्योंकि रामानंद सागर की रामायण और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत वहाँ के टेलीविजन पर भी प्रसारित होती थीं। उस समय किसी ने धर्म नहीं देखा, बस कथा देखी। कथा में अपने को देखा।

क्या यह कोई संयोग है कि आज भी पाकिस्तानी समाज का एक वर्ग इन कथाओं को न केवल पहचानता

है, बल्कि मंच पर उन्हें जीवंत भी करता है? शायद नहीं। यह ‘सामाजिक स्मृति’ का काम है – वह स्मृति जो किसी कौम के डीएनए में होती है, भले ही समय, धर्म और राजनीति उसे ढँकने की कितनी भी कोशिश करें।

सांस्कृतिक विचलन और ‘दूसरे’ की कल्पना
पाकिस्तान एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप की साझा संस्कृति का हिस्सा था। लेकिन 1951 में लियाक़त अली ख़ान की हत्या और 1971 के युद्ध के बाद, एक राष्ट्र-निर्माण की ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारत को ‘दुश्मन’ और हिंदू को ‘अन्य’ घोषित करना आवश्यक हो गया। जनरल ज़िया-उल-हक़ का दौर तो इस अलगाव का संस्थानीकरण था।

इसी प्रक्रिया में हिंदू प्रतीकों, ग्रंथों, स्मृतियों को धीरे-धीरे न केवल अस्वीकार किया गया, बल्कि उनकी जगह इस्लामिक राष्ट्रवाद को स्थायी कथानक के रूप में स्थापित किया गया। किंतु स्मृति मिटती नहीं, केवल छिपती है – और जब उसे कलात्मक स्पर्श मिलता है, तो वह फूट पड़ती है, मंच पर, रचनाओं में, या किसी अली, राणा या सम्हान के अभिनय में। ...नाटक में रावण का किरदार निभाने वाले सम्हान गाज़ी और कैकेयी का किरदार निभाने वाली सना तोहा ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। मंच-प्रस्तुति से जुड़े युवा तकनीकी सहायक अली का कहना था – ‘मैं मुसलमान हूँ, लेकिन रामायण का यह मंचन मेरे लिए किसी धर्म के विरोध में खड़े होने जैसा नहीं था। मुझे गर्व है कि मैंने एक ऐसे नाटक को मंच पर उतारते देखा, जिसने दर्शकों को जोड़ने, सोचने और संवाद की प्रेरणा दी। कला की कोई सीमा नहीं होती, और शायद यही पाकिस्तान की नई सोच की शुरुआत है।’

राणा काजमी की आस्था: संवाद का विकल्प नहीं होता

रामायण नाटक की निर्माता राणा काजमी ने कहा - ‘मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाने से कभी कोई फ़ायदा हुआ है। हम एक-दूसरे के कार्यक्रम देखते हैं, उनसे जुड़ते हैं, आनंद लेते हैं – प्रतिबंध कभी उसे नहीं रोक पाया।’

ये आवाज़ पाकिस्तान की एक नई पीढ़ी की भी हो सकती है – जो अपनी जड़ों से डरती नहीं, बल्कि उन्हें पहचानती है।

भूगोल में बसे आख्यान
रामायण और महाभारत की कई घटनाएँ आज के पाकिस्तान में घटित हुई थीं – कैकेयी का मूल राज्य केकय, भरत की मातृभूमि; तक्षशिला, जहाँ गुरु उत्तर का विद्यालय था; सिंधु और गांधार, जहाँ से महाभारत की गांधारी आई – ये स्थान राजनीतिक सीमा पार, लेकिन सांस्कृतिक केंद्र में हैं।

मंचन से ज्यादा, स्मरण था यह
कराची में राम का मंचन केवल एक नाटक नहीं था – वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक क्षणभंगुर, लेकिन तीव्र झलक थी। यह न तो भारत की ‘विजय’ थी और न पाकिस्तान की ‘पराजय’। यह आम लोगों की वह साझा स्मृति थी, जो शायद कह रही थी- ‘हम बँट ज़रूर, पर हमारे पूर्वज और उनकी कहानियाँ नहीं बँटीं।’

यह घटना बताती है कि कला और स्मृति, जब साथ आते हैं, तो सीमा नहीं देखते – केवल कथा सुनाते हैं। और कथा में, सब अपने होते हैं – राम भी, रावण भी, और सीता भी।

दृष्टिकोण	
राजेंद्र बज	
	

शैक्षणिक एवं तकनीकी विकास के दौर में आम नागरिकों की औसत बुद्धि का स्तर दिनोंदिन तर्कसंगत होता जा रहा है। अब वह दूर नहीं रहा कि एक ने कहीं और दूसरे ने मान ली। हालांकि बीते समय में विभिन्न क्षेत्रों की उच्चस्तरीय शख्सियत के बोल वचन भी ‘सत्य वचन महाराज’ की मुद्रा में अकाट्य माने जाते रहे थे। लेकिन अब किसी भी तथ्य को आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों के जेहन में हर किसी बात पर तमाम तरह के ‘किंतु परंतु’ स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो ही जाते हैं। न केवल राजनीति अपितु सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति पायी जाती है कि किसी भी स्थापित शख्सियत की अवधारणा को सर्वमान्य नहीं माना जाता। सबकी सोचने और समझने की अपनी-अपनी क्षमता है और सबके पास अपने-अपने आधार हैं।

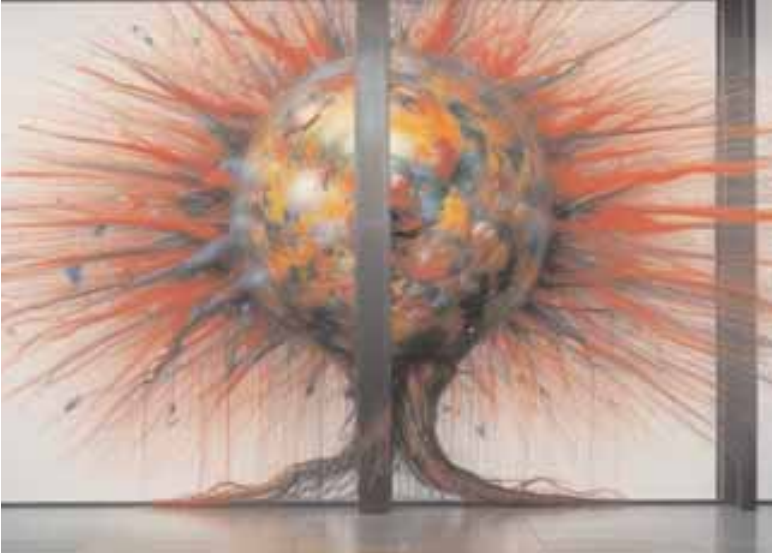
ऐसी स्थिति निर्मित हो जाने के कारणों की पड़ताल करने पर अंततः यही सिद्ध होता है कि नागरिकों की शैक्षणिक एवं तकनीकी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके चलते सदियों पुरानी अवधारणाएँ या तो सिर से ही नकारी जा रही है या फिर उसका पालन किया भी जा रहा है तो तर्क की कसौटी पर पूरी तरह कसकर। यूं भी आज जितने अति विकसित साधन-संसाधन है,

कहीं न कहीं उसके उदय में भी धर्म ग्रंथो की ही कोई प्रेरणा रही होगी। खैर, जहाँ तक दैनिक जनजीवन की बात है, अब आम नागरिकों को कपोलकल्पित बातों की अपेक्षा तार्किक बातों पर ही भरोसा होने लगा है। एक प्रकार से नागरिकों को अपने अच्छे बुरे का इल्म बहुत बेहतर तरीके से होने लगा है। यह एक सुखद स्थिति है और सुनहरे कल की ओर संकेत करती है।

यह एक स्थापित तथ्य है कि राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों में किसी भी अभिमत पर हर एक की अपनी एक विशिष्ट अवधारणा होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि इन संदर्भों में हमारे दृष्टिकोण से अन्य पक्ष भी शत-प्रतिशत रूप से सहमत हो। प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, कभी-कभी पूर्वाग्रह की प्रबलता, दुराग्रह में तब्दील भी हो जाती है -ऐसे में किसी भी विषय को लेकर तटस्थ दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं हो पाता। इन कारणों के चलते कालांतर में नागरिकों के बीच परस्पर वैचारिक टकराव की स्थिति भी निर्मित हो जाया करती है। किसी भी स्थिति में असहमतियों को कुलटना, आखिरकार नकारात्मक परिणाम का कारक होता है। ऐसी

स्थिति में परस्पर संवाद से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए।

कभी-कभी व्यक्ति विशेष के विचारों से अभिप्रेरित होकर हम अपने विचार निश्चित करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, नागरिकों की



तर्कशक्ति में आशातीत परिपक्वता भी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति को सुखद कहा जा सकता है। क्योंकि किसी भी विषय पर गहन वैचारिक मंथन उपरांत प्राप्त किए गए निष्कर्ष समाज की दशा और दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन जब ऐसे निष्कर्ष किसी अन्य पर

थोपने के किसी भी स्तर पर प्रयास किए जाते हैं, तब वैचारिक टकराव परस्पर कटुता का कारण बन जाता है। दरअसल इस स्थिति से बचने के प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में सिक्रे का दूसरा पहलू यह भी है कि वैचारिक टकराव भी

सकारात्मक परिवर्तन के कारक सिद्ध हुआ करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि नागरिकों की तर्कशक्ति में आमूलचूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अलग अलग विचारधारा को देश-प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसे हम नागरिकों की राजनीतिक चेतना के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। आमतौर पर देश प्रदेश के नेतृत्व की विचारधारा के आधार पर आम नागरिक अपना अभिमत सुनिश्चित करते हैं। लेकिन नागरिकों का ऐसा वर्ग भी है जो गहन वैचारिक मंथन उपरांत मताधिकार के माध्यम से देश-प्रदेश की दशा और दिशा को सुनिश्चित करता है। स्पष्ट रूप से एसी जागृति लोकतंत्र की बुनियाद को और

भी अधिक सशक्त आधार देने में प्रबल रूप से सहायक सिद्ध हो रही है। इन सब के मूल में मतभिन्नता के चलते ही अंततः परिवर्तन को स्वीकार किया गया है।

सामाजिक दृष्टि से अनावश्यक रूप से परिपारित की जा रही परंपराओं पर काफी हद तक अंकुश लगा है।

दरअसल विचारधारा के टकराव से भी नए निष्कर्षों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। यही कारण है कि हमने प्रत्येक रीति रिवाज और परंपराओं को तार्किक दृष्टि से आकलित करने की दृष्टि प्राप्त की है। भौतिक संसाधनों की बहुलता के बावजूद आम नागरिकों का विचार-दर्शन आस्था एवं विश्वास पर ही टिका हुआ है। यह जरूर है कि प्रगति की दौड़ में हर कोई सहभागी है, यही नहीं अपितु भौतिकवाद की प्रबलता नैतिकता को भी तार-तार कर रही है। बावजूद इसके हमारी विश्व वंदनीय भारतीय संस्कृति से आच्छादित हमारी तार्किक परंपराओं का परिपालन भी बखूबी किया जा रहा है।

परिवर्तन के दौर में दुनिया में चाहे जितने परिवर्तन आए, लेकिन हम अपनी मूलभूत सभ्यता और संस्कृति से निरंतर जुड़े रहे हैं। आज भी धर्म-अध्यात्म की दुनिया में दुनिया भर की चहल-पहल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आज भी व्रत, नियम और संयम का परिपालन किसी न किसी रूप में परिजन कर रहे हैं। माता-पिता के संस्कार बच्चों में परिलक्षित हो रहे हैं। माना कि नकारात्मकता भी है, लेकिन आज भी मर्यादित जीवन शैली को बड़ी शिद्दत के साथ आत्मसात किया जा रहा है। दरअसल राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनके मूल में कहीं न कहीं वैचारिक असहमतियाँ किसी न किसी रूप में अवश्य रही है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह कि वैचारिक मतभिन्नता का सदैव स्वागत किया जाना चाहिए।

रीना रामटेके : सामाजिक बहिष्कार बीच बनाई अपनी पहचान

अंकुरण	
सत्येन्द्र पाण्डेय	
 लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं ।	

दलित समुदाय से तात्कुक रखने वाली रीना रामटेके के परिवार को न केवल जातिगत असमानता और भेदभाव का शिकार होना पड़ा बल्कि एक समय अपने ही समुदाय द्वारा सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा। बंचित समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के कारण जब दबंगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो उन्हें जान से मारने की धमकियाँ भी दी गई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लोगों को साथ में लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया और अपने गृह नगर से पार्षद चुनी गईं। एक समय बाद जब इसकी सीमायें समझ में आईं तो सामाजिक संस्था का निर्माण किया और जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों की हकदारी के लिए प्रयास करना शुरू किया और एक बड़े इलाके में वन भूमि के निवासियों को पर्यावास अधिकार उपलब्ध कराने में भी सफल रहीं। रीना रामटेके का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुआ. उनका परिवार अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उनके अभिभावक मजदूरी करते थे और परिवार का गुजारा आसानी से नहीं चल पा रहा था। एक साथ ही सामाजिक और आर्थिक वंचनाओं के शिकार इस परिवार में जब बेटी का जन्म हुआ तो उसका बहुत उत्साहपूर्वक स्वागत तो नहीं ही किया जा सका। ट्राई जाहिर है, समाज में वर्चस्व रखने वाली पितृसत्तात्मक विचारधारा का असर रहा होगा जिसमे बेटे के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और बेटियों के पैदा होने पर परिवार में वैसी खुशी नहीं होती है। जैसे-जैसे उमर बढ़ने लगी जेंडर पर आधारित यह घरेलू असमानता स्पष्ट आकार लेने लगी और घर के कामों में बेटे के मुकाबले बेटी का समय अधिक जाया होने लगा जिसका परिणाम उनकी पढ़ाई-लिखाई पर नकारात्मक रूप से पड़ा। अपने ही घर में होने वाली लैंगिक हिंसा और भेदभाव की पीड़ा को सिर्फ उसे भोगने वाले ही महसूस करते हैं। वे समझ रही थी कि यह गलत है लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था और

रीना रामटेके का जन्म छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुआ। उनका परिवार अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। उनके अभिभावक मजदूरी करते थे और परिवार का गुजारा आसानी से नहीं चल पा रहा था। एक साथ ही सामाजिक और आर्थिक वंचनाओं के शिकार इस परिवार में जब बेटी का जन्म हुआ तो उसका बहुत उत्साहपूर्वक स्वागत तो नहीं ही किया जा सका। ट्राई जाहिर है, समाज में वर्चस्व रखने वाली पितृसत्तात्मक विचारधारा का असर रहा होगा जिसमे बेटे के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और बेटियों के पैदा होने पर परिवार में वैसी खुशी नहीं होती है। जैसे-जैसे उमर बढ़ने लगी जेंडर पर आधारित यह घरेलू असमानता स्पष्ट आकार लेने लगी और घर के कामों में बेटे के मुकाबले बेटी का समय अधिक जाया होने लगा जिसका परिणाम उनकी पढ़ाई-लिखाई पर नकारात्मक रूप से पड़ा। अपने ही घर में होने वाली लैंगिक हिंसा और भेदभाव की पीड़ा को सिर्फ उसे भोगने वाले ही महसूस करते हैं। वे समझ रही थी कि यह गलत है लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था और घरवालों से इस पर कोई स्पष्ट बात करने में भी दिक्कत तो थी ही।

घरवालों से इस पर कोई स्पष्ट बात करने में भी दिक्कत तो थी ही।

इस बीच एक और घटना हो गई। उनके पिता के बड़े पिता जी के कोई संतान नहीं थी। उनकी संपत्ति पर कुछ लोगों ने कब्जे का प्रयास किया तो रीना जी के परिवार ने स्वाभाविक रूप से विरोध किया। कब्ज़ा करने वालों का दखल जाति की सामाजिक पंचायत में मजबूत था इसलिए सामाजिक पंचायत ने इनके परिवार का बहिष्कार कर दिया। रातों-रात यह फरमान जारी कर दिया गया कि समुदाय का कोई सदस्य न तो रीना के परिवार के साथ कोई सम्बन्ध रखेगा न ही इनके साथ उठेगा-बैठेगा। इनके परिवार के साथ सामान और रुपयों-पैसों के लेन-देन पर पाबन्दी लगा दी गई थी। बहिष्कार की हद यह थी कि कोई बच्चा रीना और उनके परिवार के बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था। जाहिर है यह सब मानसिक रूप से बहुत पीड़ादायक रहा होगा।

भेदभाव के इस दोहरी मुश्किल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता उन्हें समझ में आता था कि घर की चारदीवारी से बाहर निकला जाये तभी इस घुटन से मुक्ति मिलेगी।

उन्हें बाहर निकालने का जो दरवाजा मिला वह था सिलाई सेंटर का। उनके पड़ोस की एक लड़की सिलाई सीखने जाती थी। वे भी उसके साथ जाने लगीं। इस तरह से दोनों एक दूसरे की निगरानी में थी। घरवालों को भी संतोष था। लड़की सिलाई सीख जाएगी तो उसके शादी व्याह में यह बात फायदा करेगी। यह परिवार के सपनों की सीमा थी लेकिन रीना जी के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अलग करना चाहती थी। कुछ हटकर जो उनके जीवन



को नई उंचाई प्रदान करे लेकिन सिलाई की ट्रेनिंग से उन्हें ऐसा कुछ चुनौतिपूर्ण लक्ष्य दिखाई नहीं देता था। इस बीच उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि उनकी कोई परिचित एक सामाजिक संस्था में काम करती है। यह संस्था समाज में बेहतरी के लिए काम करती है। यह बात रीना जी के लिए आकर्षक लगी और चुनौतीपूर्ण भी। घरवालों के विरोध के बावजूद वे पहुँच गईं जागृति सेवा संस्थान में साक्षात्कार देने। संयोग से उनका चयन भी हो

गया और एक नई दुनिया का रास्ता उनके लिए खुल गया।

यह समय था छत्तीसगढ़ के नए राज्य के रूप में गठन का। एक नया अवसर रीना जी के जीवन में भी इसी समय प्रवेश कर रहा था। उन्हें सबसे पहले मौका मिला रायपुर जिले के ही एक ब्लॉक में काम करने का। वे पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण और ग्राम सभाओं की बैठकों तथा निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम करती थी। यहीं उनका परिचय पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम से भी हुआ और वे उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करती थी। रास्ता नया जरूर था लेकिन समाज की मान्यताएँ वही पुरानी थी और उन्हें कदम-कदम पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती गईं।

2008 में वे मंथन संस्था से जुड़ गईं और धमतरी जिले के सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के बीच महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करती थीं। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने गरियाबंद जिले में महिलाओं की आजीविका के संवर्धन हेतु काम की शुरुआत की जहाँ मुख्य लक्ष्य था स्थानीय आजीविका और वनोत्पाद संग्रहण से महिलाओं को जोड़ते हुए समाज और परिवार में उनके सामान और निर्णयात्मक क्षमता को बढ़ाना। इन सभी कार्यों में उनको अर्पक्षित सफलता तो हासिल हो रही थी लेकिन

अनेक मामलों में निर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए मित्रों के सुझाव पर अपनी संस्था बनाने का विचार आया इसी दौरान उन्हें दलित फाउंडेशन की एक फ़ेलोशिप प्राप्त हुई जिसके तहत 30 गाँवों में रोजगार गांटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर काम करना था। उन्होंने ग्रामसभाओं को सशक्त करते हुए ग्राम स्तरीय माइक्रो प्लान तैयार किये और जाँब काई धारियों को मांग आधारित 100 दिन के रोजगार को उपलब्ध कराय। उन्होंने वन अधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार उपलब्ध कराने के लिए भी सक्रियता से काम किया। इस काम के दौरान अनेक स्तरों पर अनेक लोगों के हित और स्वार्थ प्रभावित हो रहे थे जिसके कारण उन्हें धमकियाँ मिलने लगीं ताकि वे काम बंद करके घर बैठ जाईं परन्तु इससे रीना जी का हैसला कमजोर नहीं हुआ बल्कि पत्र बढ़ती चली गईं. उनके उल्लेखनीय कार्यों के चलते 2013 में उन्हें नेशनल फाउंडेशन फॉर इंग्डिया के प्रतिष्ठित सी. सुब्रमण्यम अवार्ड से सम्मनित किया गया था।

2015 में उन्होंने गरियाबंद नगर पंचायत के पार्षद का चुनाव निर्दलीयजीता और अपना शानदार योगदान किया। अब संस्था बनाने का समय आ गया था और उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर नव निर्माण चेतना मंच का गठन कर लिया। वे अंकुरण कार्यक्रम में शामिल हुई और संस्थापिका मूल्यों के प्रसार, युवा नेतृत्व विकास तथा वन अधिकार के मुद्दों पर सघनता से काम किया। यह उनके काम का ही परिणाम है कि वन अधिकार कानून 2006 के तहत पूरे देश में तीसरा और छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को दूसरा पर्यावास अधिकार पत्र गौरला में प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 17 ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र हासिल हुए हैं।

नई शिक्षा नीति

सुनील कुमार

लेखक शिक्षाविद हैं।



भारत में नई शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को लागू हुए पाँच वर्ष हो चुके हैं। इस नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं-बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल। नीति इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि देश में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय नीति ने बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट दिशा और प्राथमिकता दी है। इससे यह व्यापक स्वीकृति बनी कि यदि हमें समग्र शैक्षिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए सभी राज्यों को 2026-27 तक एफएलएन (फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनानी थी और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि एनईपी लागू होने से पहले भी विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सर्वेक्षणों—जैसे कि असर और एनएएस—ने यह स्पष्ट किया था कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। रिपोर्टों से बार-बार यह सामने आया कि बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार पढ़ने, लिखने और गणना करने में असमर्थ हैं। इसके बावजूद लंबे समय तक इस दिशा में कोई ठोस, योजनाबद्ध और परिणामोन्मुखी प्रयास नहीं किए गए। कुछ राज्यों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पहल की, परन्तु अधिकांश

नीति इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि देश में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है और इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय नीति ने बुनियादी शिक्षा को स्पष्ट दिशा और प्राथमिकता दी है। इससे यह व्यापक स्वीकृति बनी कि यदि हमें समग्र शैक्षिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करना होगा। इसके लिए सभी राज्यों को 2026-27 तक एफएलएन (फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेसी) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना बनानी थी और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था।

स्थानों पर न ठोस योजना बनी और न ही प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। उत्तर प्रदेश का अनुभव इस दिशा में प्रेरणादायी रहा है। राज्य सरकार ने 2018-19 में ‘ग्रेडेड लर्निंग कार्यक्रम’ शुरू किया, जिसका उद्देश्य था—बच्चों की पढ़ने और गणना संबंधी बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कमजोर बच्चों के लिए प्रतिदिन 2-3 घंटे का विशेष समय निर्धारित किया गया, जिसमें उन्हें उनकी कक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि उनकी दक्षता के आधार पर समूह बनाकर पढ़ाया गया। इस प्रयास में ‘प्रथम’ संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वर्षों से ‘टीचिंग एट राइट लेवल’ पद्धति के माध्यम से प्रथम ने यह प्रमाणित किया है कि यदि बच्चों को उनकी वास्तविक शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार पढ़ाया जाए, तो उनके सीखने के स्तर में उल्लेखनीय सुधार संभव है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया और प्रथम के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से कार्यक्रम को लागू किया। एफएलएन मिशन लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश ने ‘मिशन प्रेरणा’ की शुरुआत की, जिससे विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने के लिए कार्ययोजनाएँ



बनीं। विद्यालयों की सुविधाओं में सुधार किया गया, शिक्षकों के लिए संदर्शिकाएँ विकसित की गईं और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। 2018 से 2024 के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अन्य गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कई उल्लेखनीय पहल कीं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम हमें असर 2018 और 2024 की रिपोर्टों में देखने को मिले। उदाहरण के लिए, कक्षा 3 के वे बच्चे जो कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते थे, उनकी संख्या 2018 में 28.3 प्रतिशत थी, जो 2024 में बढ़कर 34.4 प्रतिशत हो गई। घटाव का सवाल हल कर पाने वाले कक्षा 3 के बच्चों की संख्या 2018 में 26.9 प्रतिशत से बढ़कर 40.7 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, कक्षा 5 के वे छात्र जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, वे 2018 में 52.4 प्रतिशत थे, जो 2024 में बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गए। गणित में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया—भाग हल कर पाने वाले कक्षा 5 के छात्र 2018 में 29.8 प्रतिशत थे, जो 2024 में 39.5 प्रतिशत हो गए। हाल में ही जारी ‘परख’ की रिपोर्ट में भी कक्षा 3 के बच्चों के सीखने के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। यह दर्शाता है कि यदि ठोस और बच्चों की जरूरतों पर आधारित प्रयास किए जाएँ, तो सुधार न केवल संभव, बल्कि मापनीय भी है।

भोपाल के 8 ब्लैक स्पॉट पर पहुंचे न्यायमूर्ति सप्रे पूछा-एक्सीडेंट की क्या वजह?, लेफ्ट टर्न, जेबरा क्रॉसिंग-सिग्नल को भी देखा

भोपाल (नप्र)। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने शुक्रवार को भोपाल के उन ब्लैक स्पॉट को देखा, जहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। इनमें वो जगह भी शामिल हैं जहां फिर से हादसा होने का खतरा है। उन्होंने करीब 3 घंटे में 8 ब्लैक स्पॉट का जायजा लिया और अफसरों से चर्चा की। लेफ्ट टर्न, जेबरा क्रॉसिंग और सिग्नल को भी देखा। कुछ स्पॉट पर उन्होंने अफसरों से पूछा कि यहां एक्सीडेंट होने की क्या वजह है? न्यायमूर्ति सप्रे सुबह 11 बजे प्लेटिनम प्लाजा के सामने अटल पथ पर पहुंचे। यहां पहले से निगम कमिश्नर हरेंद्र नारायण, स्मार्ट सिटी सीईओ अंजू कुमार, जिप सीईओ इला तिवारी, एडीएम अंकुर मेश्राम, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बीएस कौल, एसडीएम रविशंकर राय, एसीपी अजय वाजपेयी, विजय दुबे आदि अफसर मौजूद थे। तरुण पुष्कर तिराहे पर लेफ्ट टर्न बनेगा- प्लेटिनम प्लाजा चौराहे पर न्यायमूर्ति सप्रे ने हादसों के बारे में जानकारी ली। इस पर पुलिस अफसरों ने बताया कि नेहरू नगर से अटल पथ होते हुए वाहन माता मंदिर की ओर तेजी से पहुंचते हैं। इस वजह से हादसे होते हैं। पिछले हादसों की वजह भी यही थी। यहां करीब 20 मिनट तक निरीक्षण किया। तरुण पुष्कर तिराहे पर लेफ्ट टर्न की जगह कम होने की बात सामने आई। हालांकि, एडिशनल डीसीपी कौल बोले कि स्मार्ट पोल शिफ्टिंग के बाद लेफ्ट टर्न सही किया जा रहा है। इसके बाद न्यायमूर्ति सप्रे रेडक्रास हॉस्पिटल



के पहले चौराहे पर पहुंचे। पुलिस अफसरों ने बताया कि चौराहे की रोटी को बेहतर कर रहे हैं। यहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी है। इसे अच्छी जगह पर शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। इस चौराहे पर देर रात बड़े हादसे होने की जानकारी भी दी गई। जिला कोर्ट के सामने

चौराहे पर भी लेफ्ट टर्न को बेहतर करने की बात हुई। फिर पर्यावास भवन के पास उस ब्लैक स्पॉट को देखा, जिसे डेढ़ साल पहले की बंद किया गया था। यहां से टीम सीधे अवधपुरी से पहले भेल चौराहे पर पहुंची। फिर रायसेन रोड स्थित रत्नागिरी चौराहे का निरीक्षण किया।

हादसे की वजह, मृतकों की संख्या की जानकारी ली
न्यायमूर्ति सप्रे ने निरीक्षण के दौरान हादसों की वजह, मृतकों की संख्या और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अतिक्रमण हटाने और ब्लैक स्पॉट को जल्द समाप्त करने को कहा।
तीन साल में 99 एक्सीडेंट हुए, 27 लोगों की मौत

बता दें कि पिछले तीन साल में शहर में 16 ब्लैक स्पॉट्स पर 99 हादसों में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की टीम भोपाल पहुंची है। शुक्रवार को टीम शहर में जायजा लिया। इससे पहले गुरवार को न्यायमूर्ति सप्रे ने बैठक ली थी। जिसमें भोपाल जिले में पिछले 5 साल में हुई दुर्घटनाओं, ब्लैक स्पॉट चिह्नकन एवं उनके सुधार कार्यों, चालानी कार्रवाई, जन-जागरुकता अभियानों और अन्य नवाचारों के बारे में जाना था। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है और किसी की गलती से निर्दोष की जान न जाए यह तय किया जाए।



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मानस भवन में तुलसी जयंती एवं अलंकरण समारोह को संबोधित किया।



पेंटिंग भेंट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को समत्व भवन में निफ्ट कोलकाता की छात्रा सुश्री गौरांगी शर्मा ने इंडोनेशियाई रामायण से प्रेरित भगवान श्री राम-सीता के स्वयंवर की स्वयं बनाई पेंटिंग भेंट की।

बालाघाट में दो बाइक की भिड़ंत, 3 लोगों की मौत एक गंभीर घायल का इलाज जारी, हाईवे पुलिया पर हादसा



बालाघाट (नप्र)। बालाघाट में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में लोगों की मौत हो गई। दो लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। हादसे में एक 18 वर्षीय युवक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना बालाघाट-गोंदिया हाईवे पर मंगोली धड़ी पुलिया के पास शुक्रवार दोपहर एक से दो बजे के बीच की है। एक बाइक पर सवार दो लोग खरा से रजेगांव

जा रहे थे- जानकारी के अनुसार, किरनापुर थाना क्षेत्र के खारा निवासी आईटीआई छात्र गौरव कामड़े और 19 साल का कुणाल वैद्य किसी काम से खारा से रजेगांव जा रहा था। इसी दौरान मंगोली धड़ी गांव के हाईवे पुलिया पर उनकी बाइक की दूसरी बाइक से टकरा गई। हादसे दोनों बाइक बुरी तरह से डेमेज हो गई हैं। **हादसे में इनकी हुई मौत-** हादसे में कुणाल वैद्य और ऋषभ (पिता नंदकिशोर) की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गौरव और ऋषभ के साथी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां ऋषभ के

साथी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार, मृतक ऋषभ और उसके साथी के मूल निवास स्थान का भी पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग उन्हें कर्नाटक का बता रहे हैं तो कुछ पश्चिम बंगाल का। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। घटनास्थल पर मृत हुए खारा निवासी कुणाल और ऋषभ के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए किरनापुर अस्पताल ले जाया गया है। ऋषभ के साथी का शव जिला अस्पताल में रखा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रतलाम में असिस्टेंट कमांडेंट ने की खुदकुशी की कोशिश डिप्रेशन की 50 गोлияं एक साथ खाई सीनियर अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप

रतलाम (नप्र)। रतलाम के जावरा में 24वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट रामबाबू पाठक के बाॅम्बे हॉस्पिटल भेजा गया है। रामबाबू की बेटी मुस्कान और परिजन एम्बुलेंस से लेकर उन्हें रवाना हुए हैं। उनका एक बेटा भी है जो भोपाल में रहता है। वो खबर मिलते ही इंदौर के लिए रवाना हो गया। असािस्टेंट कमांडेंट की पत्नी और बेटी ने बटालियन के सीनियर अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लगातार इश्टी के चलते रामबाबू डिप्रेशन में थे। शुक्रवार सुबह रामबाबू बटालियन को परेड में शामिल हुए थे। बताया जा रहा



है कि उन्होंने सुसाइड नोट फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। बेटी मुस्कान ने बताया कि पापा ने दुनिया छोड़ कर जाने का एक लेटर लिखा है। **रोज कहते थे लाइफ खत्म कर लूंगा-** रामबाबू की बेटी ने कहा- हमारे पास उनके डिप्रेशन में रहने के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्टर तक ने इश्टी करने के लिए मना किया था, लेकिन विभाग ने उसे बहाना बताया। उन्होंने वीआरएस लेने का भी विचार किया था। वो रोज बोलते थे कि मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूंगा। हम एसपी सर को भी बताकर आए थे।

भिंड रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे लेटकर सुसाइड इटावा-कोटा पैसेंजर के चलते ही ट्रैक पर लेटा, सिर और धड़ अलग हुआ

भिंड (नप्र)। भिंड रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के चलते ही पटरी पर अपना सिर रख दिया। ट्रेन का पहिया उसकी गर्दन के ऊपर से गुजर गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है। मनेपुरा गांव के रहने वाले राजीव जोशी (45) ने ट्रेन से कटककर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक समस्याओं के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहा था।

ट्रेन के चलते ही ट्रैक पर रखा सिर
रेलवे पुलिस थाना प्रभारी प्रीतम सिंह भदौरिया ने बताया कि राजीव जोशी करीब एक घंटे से स्टेशन पर बैठा हुआ था। शाम करीब 5:30 बजे इटावा-कोटा पैसेंजर ट्रेन के आने पर वह ट्रेन में चढ़ा और फिर दूसरी तरफ उतर गया। काफी देर तक घूमने के बाद शाम साढ़े पांच बजे जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वह नीचे लेट गया। उसने ट्रैक पर अपना सिर रख दिया।

स्टेशन पर मची अफरा-तफरी
घटना के बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची। स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की पहचान की गई और परिजनों को सूचित किया गया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के पहुंचने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

एमपी के सांसदों की दिल्ली में बैठक बीएल संतोष ने पूछा- किसी दूसरे सांसद के नवाचार बताएं, राजगढ़ सांसद की हुई तारीफ

भोपाल (नप्र)। दिल्ली में मप्र के सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, जगदीश देवड़ा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय और लोकसभा-राज्यसभा के सांसद गण मौजूद थे। **संतोष ने सांसदों से पूछा- किसी दूसरे सांसद के नवाचार बताएं-** बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सांसदों से कहा अपने राज्य के किसी दूसरे सांसद द्वारा किए गए नवाचार के बारे में बताएं। इस दौरान एक सांसद ने राजगढ़ सांसद रोडमल नागर द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में स्थानीय रोजगारों और वोकल फॉर लोकल को लेकर किए गए नवाचार के बारे में बताया। **सांसदों से पूछा- टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं?**- बीएल संतोष ने सांसदों से पूछा कि जब आप दिल्ली में रहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं?। संसदीय क्षेत्र बड़ा होता है तो प्रवास और दौरो के कार्यक्रमों की प्लानिंग कैसे करते हैं। संतोष ने सांसदों से पूछा कि एमपीलेट फंड के आवंटन किस तरह करते हैं। **ये सांसद और केन्द्रीय मंत्री रहे मौजूद-** केन्द्रीय मंत्री: शिवराज सिंह चौहान, दुर्गादास उड्डेक, डॉ. वीरेन्द्र कुमार खटीक, सावित्री ठाकुर, एल मुरुगन लोकसभा सांसद वीडी शर्मा (खजुराहो), राजेश मिश्रा (सीधी), रोडमल नागर (राजगढ़), जनेश्वर



पाटिल (खंडवा), राहुल सिंह लोधी (दमोह), शिवमंगल सिंह तोमर (मुरैना), दर्शन सिंह चौधरी (होशंगाबाद), बंटी साहू (छिंदवाड़ा), आलोक शर्मा (भोपाल), गणेश सिंह (सतना), आशीष दुबे (जबलपुर), हिमाद्री सिंह (शहडोल), जनार्दन मिश्रा (रीवा),अनीता चौहान (झाबुआ), शंकर लालवानी (इंदौर), अनिल फिरोजिया (उज्जैन), भारत सिंह कुशवाह (ग्वालियर), गजेन्द्र

सिंह पटेल (खरगोन), फगन सिंह कुलस्ते (मंडला), सुधीर गुप्ता (मंदसौर), भारती पारदी (बालाघाट), संस्था राय (भिंड), लता वानखेड़े (सागर), महेन्द्र सिंह सोलंकी (देवास) राज्यसभा सांसद: डॉ. उमेश नाथ महाराज, सुमेर सिंह सोलंकी, कविता पाटीदार, सुमित्रा बाल्मीकि, माया नारियलिया।

